>

Title: Need to raise the Minimum Support Price for paddy.

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : देश में किसानों की माली हालत दिनों-दिन खराब होती जा रही, वÂाों से किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। उनको उत्पादित की गई रबी व खरीफ की फसल-गेहूं, धान, चना, दाल को लागत कीमत से भी कम कीमत पर बाजार में बेचना पड़ रहा है। क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कम है। किसान की फसल का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार निर्धारित करती है। जबकि उद्योग-कारखानों में उत्पादित सामान की कीमत उद्योगपति स्वयं निर्धारित करते हैं। किसान एवं उद्योगपति में अंतर नहीं है। केन्द्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1000 प्रति कुन्तल निर्धारित किया है।

धान की फसल छत्तीसगढ़, पं0 बंगाल, आध्र प्रदेश, बिहार, महाराÂट्र आदि प्रदेशों में बहुत ज्यादास मात्रा में पैदा की जाती है। जो विदेश तक में निर्यात की जाती है।

छत्तीसगढ़ में धान का उत्यधिक उत्पादन होने के कारण् इसे धान का कठोरा कहा जाता है।

धान की फसल का समर्थन मूल्य कम होने से किसान उदास एवं हताश है। केन्द्र सरकार फसल का लागत के अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारित करने की दिशा में गंभीरता से विचार करे। मोटे धान का समर्थन मूल्य 1000 रु पए प्रति क्विंटल तथा पतले धान का समर्थन मूल्य 1500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए एवं किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाए।